3

"सौगात-ए-मोदी": बांटी खुशियाँ

5

सिनेमा में फ्लॉप राजनीति में चमके

6

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 47 | प्रति सोमवार, 31 मार्च 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे अपने ही सहयोगी

▪ गृहमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री साव और अन्य अफसरों की मिलीभगत, साख पर लगा रहे बट्टा

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

अपने लगभग 15 महीने से अधिक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य को दोबारा से विकास की पटरी पर लाने का प्रयास किया है। यह साय की सक्रियता और समर्पण का ही परिणाम है कि आज राज्य तरक्की कर रहा है। राज्य सरकार की हो या फिर केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक कैसे पहुंचे साय हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। हालांकि साय कैबिनेट के कुछ नेता ही कहीं न कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री साय से लेकर उनकी सरकार के कार्यों तक को ढंग से पूरा न कर बेदाग मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। अगर समय रहते मुख्यमंत्री साय नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब उनके अपने ही उन्हें आस्तीन का सांप बनकर डस लेंगे।

बेदाग छवि के मुख्यमंत्री हैं साय

मुख्यमंत्री साय का मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को मिलना यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। साय वह मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरह से बेदाग हैं और जनता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। सर्व जन हिताय...के सूत्र को आत्मसात करते हुए साय प्रधानमंत्री मोदी की मंशा अनुरूप अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के कार्य में अग्रसर हैं।

अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे साय

विगत एक वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। वास्तव में प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष का समय विश्वास के संकट का समय था। पूर्ववर्ती सरकार ने 'जन घोषणा पत्र' में किए गए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए ही भरोसे का संकट पैदा कर दिया था। देखा जाये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जनता में इस विश्वास को कायम करने की थी। अब एक वर्ष पूरे होने पर जब आपके माध्यम से जनता के समक्ष हमारी पूरी सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रस्तुत हुई है। (शेष पेज 3 पर)

कृषि मंत्री कंसाना के संरक्षण में चल रहे अवैध रेत उत्खनन के कार्य से वन विभाग ने उठाया पर्दा

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में नर्मदापुरम से लेकर मुरैना चंबल तक अवैध रेत खनन का खुला का खेल चल रहा है। यह खेल आज से नहीं बल्कि पिछले 20 वर्षों से चल रह है जिस पर अंकुश लगाने में पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार नाकाम रही और अभी तक डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस दिशा में कोई विचार तक नहीं किया है। यही कारण है कि खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण मध्यप्रदेश को आज माफियाओं की नजर लग गई है। जिसे देखो वही अपने ढंग से प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ। आज यह विषय इसलिए सामने आया क्योंकि प्रदेश के ही कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के पुत्र द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे रेत खनन के कार्य से पर्दा उठ गया है। पिछले दिनों वन विभाग की एक टीम ने जिस डंफर चालक को रेत ले जाते हुए पकड़ा उसने होश उड़ा देने वाले राज खोले। ड्राइवर ने बताया कि यह डंफर बंकू कंसाना यानि प्रदेश के कृषि मंत्री के सुपुत्र का है।

▪ पुत्र कप्तान कंसाना पहुंचा रहे प्राकृतिक संपदा को नुकसान

क्या है पूरा मामला

दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने नेशनल हाइवे- 44 के पास कच्चे रास्ते से रेत ले जा रहे एक डंपर को पकड़ा। डंपर चालक दीवान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह वाहन राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बड़े बेटे बंकू उर्फ कप्तान कंसाना का है। इस घटना ने न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। दरअसल, वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान चंबल नदी से रेत ले जा रहे डंपर को देखा। पीछा करने के बाद उसे एनएच-44 पर रोक लिया गया। डंपर को जब्त कर डिपो लाया गया, जहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने ड्राइवर दीवान से पूछताछ की। ड्राइवर ने कहा, "यह डंपर बंकू भैया का है, जो मंत्री एदल सिंह कंसाना का बेटा है। मुझे हर दिन रेत भरकर उनके बताए स्थान पर डालना होता था। इसके बदले मुझे रोज 1000 रुपए मिलते थे।" उसने आगे बताया कि वह हाल ही में बायपास सड़क बनाने वाले प्लांट पर रेत डाल रहा था। (शेष पेज 2 पर)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार के मामलों में अब फंस गये बेटे चेतन्य बघेल उर्फ बिट्टू

▪ कांग्रेस आलाकमान की आंख में पट्टी बांध पांच साल तक राज्य में बघेल ने मचाया भ्रष्टाचार का आतंक

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जहां नान घोटाला, पीएससी घोटाला, अनाज घोटाला, धान घोटाला, कोयला घोटाला सहित महादेव ऐप जैसे घोटालों को अंजाम दिया। वहीं, अब एक के बाद एक उन्हें उनके पापों की सजा मिलती दिखाई पड़ रही है। चर्चा इस बात की है कि पिछले दिनों आयकर विभाग द्वारा उनके बेटे चैतन्य बघेल के यहां जो छापेमार कार्रवाई हुई उसके बाद बघेल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। (शेष पेज 2 पर)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार के मामलों में अब फंस गये बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू

शीर्ष नेता समय से नहीं चेते तो मप्र, राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का अस्तित्व होगा खत्म

(पेज 1 से जारी)

चिंता का विषय यह है कि बघेल द्वारा राज्य में पांच साल के कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए उन सभी की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को होने के बाद भी आलाकमान के लोगों ने आंख पर पट्टी बांध रखी है। यही कारण है कि न तो बघेल को प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने जैसा कोई कदम उठाया है और न ही आलाकमान ने उनसे इस विषय पर कोई पूछताछ की है।

अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव को कमान दे देना चाहिए। यही वह समय है जब प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। छत्तीसगढ़ का हाल भी मध्यप्रदेश या राजस्थान जैसी हो सकती है।

क्या चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के हाथों में सौंपना चाहिए कांग्रेस की कमान?

राज्य में कांग्रेस का अस्तित्व पड़ गया संकट में

जिस ढंग से बघेल ने पांच वर्षों के कार्यकाल में राज्य में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया उसके बाद तो पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने की स्थिति बन गई है। अगर पार्टी आलाकमान समय रहते नहीं चेता तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का अस्तित्व मप्र, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, भूपेश बघेल के कार्यकाल की बारीकी से समीक्षा करें और आंखों पर बंधी पट्टी को खोलकर उनका विश्लेषण उपरांत यह तय करें कि बघेल को किस तरह से पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि यदि पार्टी में बघेल जैसे भ्रष्टाचारी नेता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पार्टी आगामी चुनाव में जनता के दरवाजे पर जाने लायक भी नहीं बचेगी।

बघेल के 14 ठिकानों पर एक साथ मारे छापे

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड की है। चैतन्य के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। छापेमारी छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में की गई है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे का नाम भी सामने आया है। ईडी ने चैतन्य बघेल के ठिकानों सहित छत्तीसगढ़ में 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप है कि इसमें 2019 और 2022 के बीच राज्य के खजाने से करीब 2,161 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनका संबंध चैतन्य बघेल से है। एजेंसी ने मौजूदा सबूतों को तलाशी का आधार बताया है। ईडी की जांच में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं और आबकारी विभाग के अधिकारियों से जुड़े एक नेटवर्क का भी पता चला है।

डुप्लीकेट होलोग्राम का हुआ इस्तेमाल

इस रिडिकेट पर एक 'समानांतर' आबकारी प्रणाली संचालित करने का आरोप है, जिसमें बिना सही डॉक्यूमेंट्स के सरकारी दुकानों के जरिए बेहिसाब शराब बेची गई। इससे छत्तीसगढ़ को राजस्व का काफी नुकसान हुआ। कथित तौर पर इस सिस्टम में अवैध शराब की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए डुप्लिकेट होलोग्राम और बोतलों का इस्तेमाल भी शामिल था। ईडी ने जुलाई 2023 में अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी जैसे प्रमुख व्यक्तियों का नाम शामिल था। एजेंसी ने दावा किया था कि इन लोगों ने ही घोटाले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें खरीद प्रक्रियाओं में हेरफेर करना और चुनिंदा शराब निर्माताओं से कमीशन लेना शामिल था।

ब्यूरोक्रेट्स-व्यापारी आए जद में

कथित घोटाले के मामले में एक्शन लेते हुए में एजेंसी ने व्यापारियों और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स सहित अलग-अलग आरोपियों से जुड़ी करीब 205.49 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। इन संपत्तियों में चल और अचल दोनों शामिल हैं। चैतन्य बघेल के खिलाफ हुई इस छापेमारी से प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता के मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहले ही घोटाले से जुड़े आरोपों से इनकार कर चुके हैं। वह ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखमा पर घोटाले से 72 करोड़ रुपए हासिल करने का आरोप है।

कृषि मंत्री कंसाना के संरक्षण में चल रहे अवैध रेत उत्खनन के कार्य से वन विभाग ने उठाया पर्दा

(पेज 1 से जारी)

ड्राइवर के मुताबिक, चंबल से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिसमें लोडर भी लगे हैं। डंपर पर "SS Kansana" और 'बंकू' लिखा था, साथ ही दो मोबाइल नंबर (7049551111 और 9425144665) भी अंकित थे।

कंसाना के सुपुत्र ने किया आरोपों का खंडन

इस मामले में बंकू कंसाना ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, "इस डंपर से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, न ही मैं इस ड्राइवर को जानता हूं। सुबह 7:30 बजे मुझे इसकी जानकारी मिली। वीडियो में कुछ लोग ड्राइवर पर मेरा नाम लेने का दबाव बनाते दिख रहे हैं। यह ट्रक मेरा नहीं है। जांच से पता चला कि यह कैलारस के जंडेल सिंह कुशवाह का है। मैं रेत का व्यापार नहीं करता। ट्रक पर मेरा नंबर लिखा है, लेकिन कोई भी इसे लिख सकता है। यह एक साजिश है। मैं इसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, मेरे वकील से बात हो गई है।

लगातार हो रहा है अवैध उत्खनन

वन विभाग के एसडीओ भूरा गायकवाड़ ने कहा, "हमने रेत से भरा डंपर पकड़ा और चालक को गिरफ्तार किया। डंपर का मालिक कौन है, यह जांच का विषय है। वह नेता हो सकता है या नहीं भी। हम इसकी तह तक जाएंगे।" हालांकि, ऑफ-कैमरा अधिकारियों ने ड्राइवर के बयान को सही माना। यह कार्रवाई चंबल में अवैध रेत उत्खनन पर लगातार हो रही किरकिरी के बाद की गई।

कंसाना शब्द के कारण शुरू हुई सियासत

इस पूरे घटनाक्रम में मंत्री कंसाना के शामिल होने का अंदेशा लगते ही कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से सक्रिय हो गये हैं और उन्होंने कंसाना और मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने हाल ही में भोपाल में कहा था, "मुरैना में कोई रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया हैं जो पेट पालते हैं।" इस बयान के बाद अब उनके बेटे का नाम सामने आने से विवाद बढ़ गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, "रेत माफिया को पेट माफिया कहने वाले मंत्री का बेटा भी रेत की माफियागिरी से पेट पाल रहा है। ट्रक पर नाम और ड्राइवर का बयान सबूत हैं। जब मंत्री का घर ही रेत से चल रहा हो तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी?" कांग्रेस ने इसे सरकारी संरक्षण का उदाहरण बताया।

पहले भी लगे हैं आरोप

एंदल सिंह कंसाना और उनके परिजनों पर पहले भी अवैध रेत से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। बंकू पर तीन साल पहले राजस्थान के धौलपुर में पुलिस से ट्रक छुड़ाने का केस दर्ज हुआ था। मुरैना के सराय छोला थाने में भी ऐसा ही मामला दर्ज है, लेकिन प्रभाव के चलते हर बार क्लीनचिट मिली। उनके नाती केपी कंसाना पर सीबीआई में भी केस दर्ज हो चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे अपने ही सहयोगी

(पेज 1 से जारी)

गृहमंत्री शर्मा बने आस्तीन का सांप

एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां जनता के कल्याण के लिए हितकारी फैसले ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गृहमंत्री विजय शर्मा और उनके समर्थक जनता को डरा धमका कर अवैध वसूली कर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का नाम खराब करने में जुटे हुए हैं। नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि गृहमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ईमानदारी और कर्मठता से परेशान हैं। वे लगातार भ्रष्टाचार का बीज रोपने का प्रयास करते हैं लेकिन ईमानदार की मिसाल बने विष्णुदेव साय हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। वे मुख्यमंत्री बनने तक का सपना देख रहे हैं। ऐसे में आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि प्रदेश में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, भ्रष्टाचार का फैलता जाल और जनता की हितकारी योजनाओं में सेंध लगाने का कार्य यह दोनों ही कर रहे हैं।

कुछ अफसरों के शामिल होने की भी आशंका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद के काम और अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों तथा अफसरों बेहद भरोसा करते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि जनता के हितों को किस तरह से साधा जाये और उनकी खुशहाली के लिए कैसे कार्य किया जाये। लेकिन राज्य में योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले कुछ अफसर जानबूझकर उनकी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय को इन बाधाओं को समझना होगा और जल्द ही ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना होगा जो उनके और पार्टी के लिए आने वाले समय में खतरा बन जाये।

यह जनकल्याण कार्यों को पूरा कर चुके हैं साय

साय ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरु करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है, इससे पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेंगे और ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी..उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से क्लीयरेंस लेना होगा, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी। इसके अलावा ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत बना दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाः मुख्यमंत्री साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैंक ऑडिट एंड एआई' को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीएसटी और कर सुधारों ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया है और राजस्व संग्रहण को मजबूत किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत की इस विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में भी उनकी भागीदारी अहम होगी। यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने सीए छत्तीसगढ़ के विशेष लोगो का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बौद्धिक वर्ग हमेशा नई तकनीकों को अपनाता है और एआई (AI) ऐसी ही एक गेम-चेंजर तकनीक है। उन्होंने माना कि एआई न केवल सीए पेशे को और सशक्त करेगा, बल्कि इस क्षेत्र की गुणवत्ता व गति को भी बढ़ाएगा। उन्होंने एआई से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने आईसीएआई की स्थापना को भारतीय अकाउंटिंग क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि 1949 में 1600 लोगों के साथ शुरू हुआ यह संस्थान आज चार लाख से अधिक सदस्यों का मजबूत संगठन बन चुका है, जो देशभर में आर्थिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति से बढ़ा निवेश, प्रदेश को 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। नीति निवेशकों के लिए आकर्षक है और सभी वर्गों का ध्यान रखती है। अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज की उपलब्धता और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्थापना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में राज्य सरकार ने कई दूरदर्शी फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो रहा है।

विकसित भारत में प्रदेश की महती भूमिकाः मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ विज़न डॉक्यूमेंट 2047 का ज़िक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदेश के 3,000 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें भागीदार बनेंगे। आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने संस्था की स्थापना (1949) से लेकर अब तक की विकास यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्य से जुड़ी चुनौतियों और दायित्वों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि देश के सभी सीए मिलकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।

"सौगात-ए-मोदी" के तहत मुस्लिम बहनों को बांटी खुशियाँ

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल "सौगात-ए-मोदी" के तहत मुख्यमंत्री साय ने गरीब महिलाओं को गिफ्ट पैकेट वितरित किए जिसमें लेडीज सूट का कपड़ा, सेवइयां, खजूर और मिठाइयां शामिल थीं। मुख्यमंत्री साय ने सभी को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद का पर्व प्रेम, सद्भाव और एकजुटता का प्रतीक है। डॉ. सलीम राज ने बताया कि इसके पहले रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 500 महिलाओं को गिफ्ट पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद, एम. इकबाल, संजय श्रीवास्तव, शाहिद खान, रजिया खान, आबिदा खान सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

सम्पादकीय

क्या सिर्फ जल है तो कल है कह देने से हमारा भविष्य सुरक्षित है?

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक वैश्विक पहल के तहत वर्ष 1993 में की गई थी। इस दिवस के बहाने विभिन्न केंद्रीय विषयों या थीम के साथ मीठे जल के महत्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ज्ञात है, एक समय था जब कुओं, तालाबों, नालों, नदियों और अन्य जलस्रोतों में साफ जल उपलब्ध होता था, लेकिन अब स्थिति व्यापक रूप से बदल गई है। मात्रा या गुणवत्ता के संबंध में जल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई है, जो जल की कमी या जल संकट के रूप में प्रकट होती है। जल इतिहास के हर खंड में कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं— जैसे सिंधु, नील, दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यताएँ के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन रहा है। यह भी सच है कि इन सभ्यताओं में जल संसाधन के कारण संघर्ष भी उत्पन्न हुए, जैसे कि मेसोपोटामिया के लक्षण और उम्मा शहरों के बीच तनाव का स्पष्ट लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यह संघर्ष, जो मानव इतिहास के सबसे पुराने ज्ञात युद्धों में से एक है, भूमि और जल संसाधनों के एक उर्वर खंड के आसपास केंद्रित था।

पानी हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की सकती। कहने को तो पृथ्वी में 70 फीसदी पानी है लेकिन पीने का पानी 01 फीसदी से भी कम है।

ग्लोबल वॉर्मिंग और बढ़ते प्रदूषण के चलते पीने के साफ पानी की और भी ज्यादा किल्लत होते जा रही है। आज यानी 22 मार्च को दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे देश के बारे में जहां पीने का पानी आसानी से मिल जाता है। साफ पीने के पानी के बढ़ती कमी को दिखाते हुए हर साल 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के दो अरब से ज्यादा लोग पीने का साफ पानी नहीं पी पाते। यही नहीं रिपोर्ट की माने तो हर दो मिनट में पांच साल से कम उम्र के एक बच्चे की मौत अस्वच्छ पानी पीने से होती है। इस साल 2025 में विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है।

जब स्वच्छ पेयजल की बात आती है, तो यूरोप में हम बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया में सबसे स्वच्छ पेयजल वाले शीर्ष 10 देश सभी यूरोप में हैं। इन देशों में अक्सर बहुत स्वच्छ और शुद्ध जल स्रोतों तक पहुँच होती है, जैसे कि पहाड़ी झीलें, और पानी को अच्छी तरह से उपचारित करने के लिए वित्तीय संसाधन और तकनीक होती है। इसलिए नीचे सूचीबद्ध देशों में, नल के पानी में रोगजनकों या विषाक्त पदार्थों के बारे में चिंतित होने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। साफ पीने के पानी के मामले में भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इस लिस्ट में हमारे देश का 139वां स्थान है। वहीं पानी की खपत के मामले में भारत 10वें नंबर पर आता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम 144वें नंबर पर और चीन का नंबर 54वें स्थान पर आता है।

सियासी गहमागहमी

सरकार में मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं खान

प्रदेश सरकार में चर्चा का विषय रहने वाले अफसर नियाज अहमद खान एक बार अपने बयानों के कारण चर्चा में आ गये हैं। कभी अबु सलेम को लेकर तो कभी हिंदु-मुस्लिम धर्म आदि विषयों पर बयानबाजी कर अलग-अलग सरकारों को कठघरे में खड़ा कर देने वाले नियाज अहमद साहब कि दाल फिलहाल मोहन सरकार में गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह पहला अवसर नहीं है जब नियाज साहब ने हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान दिया हो, इससे पहले शिवराज सरकार में भी वे हिंदुओं के पक्ष में टिप्पणी कर चुके हैं लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें कभी कोई विशेष स्थान दिया ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी में हमेशा इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि आखिर नियाज अहमद खान से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिससे वे खुद को मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं। खैर, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि सरकार को खान को मुख्य धारा से जोड़ती है या फिर वह इसी तरह से खुद को अकेला महसूस करते रहेंगे।

दिल्ली से लगी प्रहलाद पटेल को जबरदस्त फटकार

पिछले दिनों जनता को भिखारी शब्द का उपयोग कर संबोधित करने वाले मोहन सरकार में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को अपनी इस कथनी के बाद न सिर्फ समाज में बल्कि पार्टी में भी खासा शर्मिंदा होना पड़ा। पार्टी आलाकमान ने पटेल को स्पष्ट तौर पर हिदायत तक दे दी है, कि दोबारा अगर वे सार्वजनिक ढंग से इस रह के बयानबाजी करते दिखाई दिये तो उन पर पार्टी के नियमों के उल्लंघन करने की कार्यवाही होगी। चर्चा इस बात की भी है कि आलाकमान को पटेल ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सके और आलाकमान ने उन्हें चेतावनी देते हुए वापस प्रदेश भेज दिया।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह आधार को मतदाता पहचान-पत्र से जोड़ेगा।

कांग्रेस और भारतीय राजनीतिक दल मतदाता सूचियों के मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं, जिनमें अनावश्यक रूप से अधिक संख्या में नाम जोड़ना, अपरावर्तित रूप से नाम हटाना और मतदाता पहचान-पत्रों की नकल करना शामिल है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

शिक्षा और किताबों के बाजार में पारदर्शिता की आवश्यकता !
पिछले कुछ वर्षों से कई निजी स्कूलों ने बच्चों के लिए जरूरी किताबों और कॉपी की खरीदारी के लिए कुछ खास डिपो निश्चित है, इन डिपो में दुकानदार अपनी मनमर्जी के अनुसार कीमतें वसूलते है, जिससे अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है!

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

सिनेमा के पर्दे पर फ्लॉप हुए चिराग ने राजनीति में बिखेरी अपनी चमक

समता पाठक/जगत प्रवाह

पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति से केन्द्र की सत्ता में पहुंचे लोजपा पार्टी के प्रतिनिधि चिराग पासवान वर्तमान में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1.70 लाख वोटों से जीत हासिल की। पीएम मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चिराग सक्रिय राजनीति में आने के पहले बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रह चुके हैं। फिल्मी दुनिया से करियर की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान अब अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद सबसे पहले 2014 में जमुई लोकसभा सीट से लोजपा टिकट पर चुनाव लड़ा। फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में चिराग पासवान को पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली। वर्ष 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में भी जमुई सीट पर उन्होंने अपना कब्जा कायम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मतभेद उत्पन्न हो गया। 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा में नेता के रूप में घोषित कर दिया। जिसे बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था।

राजनीति में कामयाब होने वाले चिराग बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। चिराग ने 2011 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म 'मिले ना मिले हम' में एक साथ काम किया था। तनवीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। वही इस फिल्म में कंगना, चिराग के अलावा पूनम ढिल्लों, सागरिका घटगे, कबीर बेदी, नीरू बाजवा, दलीप ताहिल, सुरेश मेनन, कुणाल कुमार ने भी अलग-अलग भूमिका अदा की थी। राजनीति के साथ चिराग समाज के लिए भी काम करते हैं। वे अपने नाम से एक NGO का संचालन करते हैं जिसका नाम है 'चिराग का रोजगार' जो उनके राज्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करता है।

नववर्ष के संकल्पों को पूरा करने का दिव्य अवसर गुड़ी पड़वा-चैत्र नवरात्रि

▪ नववर्ष, नवसंकल्प और नवऊर्जा का का प्रतीक

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

गुड़ी पड़वा का पावन पर्व न केवल हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, बल्कि यह एक नए जीवन का संदेश भी लेकर आता है। यह वह समय है जब प्रकृति नवपल्लवित होती है, चारों ओर नवजीवन का संचार होता है। ठीक इसी तरह, यह हमारे लिए भी नए लक्ष्यों, नए सपनों और नए संकल्पों को साकार करने का सर्वोत्तम समय है। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का पर्व है, जो हमें आंतरिक शक्ति, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का संदेश देती है। यह नवरात्रि रामनवमी के साथ समाप्त होती है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों—शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये नौ देवियां हमें जीवन के नौ गुण सिखाती हैं—संयम, तप, साहस, शांति, समृद्धि, प्रेम, न्याय, शक्ति और सिद्धि।

ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की गहराई

यह सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी पवित्र तिथि पर ब्रह्माजी ने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह नए आरंभ और सृजन का पावन दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, और कुछ स्थानों पर उनके मत्स्य अवतार का स्मरण किया जाता है। इसी दिन, पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर न्याय और धर्म की स्थापना की थी, और विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ, जो हमारी काल गणना का आधार है। कुछ क्षेत्रों में यह शालिवाहन शक संवत की शुरुआत का भी स्मरण कराता है। महाराष्ट्र में तो यह दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय और मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है, जहाँ घरों पर भगवा ध्वज फहराकर अपनी जीत का उत्सव मनाया जाता है। यह दिन इतना शुभ और मंगलकारी माना जाता है कि लोग इस दिन नए व्यापार शुरू करते हैं, नए घरों में प्रवेश करते हैं, और अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ करते हैं।

नए साल में अपने संकल्पों को कैसे पूरा करें

1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें

सफलता का पहला चरण है—एक स्पष्ट लक्ष्य। नववर्ष के पहले दिन ही यह तय करें कि इस साल आप क्या हासिल करना चाहते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा या आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हो, अपने उद्देश्य को लिखें और उसे दृढ़ता से याद रखें।

2. छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करें

बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लें। हो सकता एक छोटा काम करें जो आपको आपके मुख्य उद्देश्य के करीब ले जाए। जैसे—अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना है, तो प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने का संकल्प लें।

3. अनुशासन और नियमितता बनाए रखें

मां दुर्गा की साधना हमें अनुशासन का महत्व सिखाती है। सफलता के लिए नियमित प्रयास जरूरी है। एक बार संकल्प लेने के बाद, उस पर अडिग रहें।

4. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास

नकारात्मक विचारों को दूर रखें। रामायण से सीखें कि भगवान राम ने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न रही हों। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है।

5. प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान

नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। यह आपको

नवरात्रि: 9 दिन, 9 संकल्प

- अनुशासन बढ़ाएं
- स्वाध्याय करें
- आत्मविश्वास बढ़ाएं
- स्वास्थ्य का ध्यान रखें
- परिवार के साथ समय बिताएं
- धैर्य बढ़ाएं
- आत्मसुधार करें
- कृतज्ञता व्यक्त करें
- नई उम्मीद, नई जीत

चैत्र नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हर अंधकार के बाद एक नया प्रकाश होता है, हर संघर्ष के बाद एक नई विजय होती है। इस नववर्ष में, अपने संकल्पों को दृढ़ता से पकड़ें और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मां दुर्गा की कृपा और भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ हो।

"जीत उसी की होती है, जो हार मानने से इनकार कर देता है।"

इस नववर्ष में, आपका हर लक्ष्य पूरा हो, हर मनोकामना सिद्ध हो— यही शुभकामना

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। रिजिजू ने इस मुद्दे को बारी-बारी से संसद के दोनों सदनों में उठाया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परंतु कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐसा करने जा रही है। संविधान बदलने का बयान संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है।' यही नहीं कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया था। जबकि हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है। अतएव इस तरह के प्रयास संविधान निर्माताओं की देशहित से जुड़ी इच्छाओं के विरुद्ध हैं। बावजूद कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने का तुष्टिकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है।

कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 से 2010 के बीच में कांग्रेस ने चार बार आंध्रप्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए? दरअसल यह कांग्रेस का 'पायलट प्रोजेक्ट' था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा हमेशा रही है। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस मंशा को पलीता लगता रहा है। इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर आपील को खारीज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए कि उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या इस तरह कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा?

दरअसल आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर' आरक्षण का लाभ संविधान के विरुद्ध बताया था। दिसम्बर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया है कि 'अल्पसंख्यकों से संबंधित' और 'अल्पसंख्यकों के लिए' जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था।

वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, उनको बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में केवल पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालत करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इसी भेद को दूर करने की पैरवी करती है।

वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केन्द्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुरतैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं। इस नाते 'अल्पसंख्यक श्रेणी' का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक निहितार्थ हैं, इन्हें समझना मुश्किल है। यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर जैन धर्मावलंबियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाती हैं।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का आधार जिस मिश्र आयोग को बनाया गया था, उसका गठन 'जांच आयोग के तहत' नहीं हुआ था। दरअसल इस रपट का मकसद केवल इतना था कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर व पिछड़े तबकों की पहचान कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सहित अन्य जरूरी कल्याणकारी उपाय सुझाये जाएं। जिससे उनका सामाजिक स्तर सम्मानजनक स्थिति हासिल कर ले। इस नजरिये से सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों का औसत अनुपात बेहद कम है। गोया संविधान में सामाजिक और शैक्षिक शब्दों के साथ 'पिछड़ा' शब्द की शर्त का उल्लेख किये बिना इन्हें पिछड़ा माना जाकर अल्पसंख्यक समुदायों को 15 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें से 10 फीसदी केवल मुसलमानों को और पांच फीसदी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिए जाने का प्रावधान तय हो। शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण की यही व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। यदि इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आती है तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जो 27 प्रतिशत की सुविधा हासिल है, उसमें कटौती कर 4.5 प्रतिशत की दावेदारी अल्पसंख्यकों की तय हो? हालांकि वर्तमान में कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। चूंकि सच्चर समिति की रिपोर्ट मिश्र आयोग के गठन से पहले आ गई थी इसलिए इस रिपोर्ट को विपक्ष सच्चर समिति को अमली जामा पहनाने के रूप में भी देखा था। सच्चर और मिश्र रिपोर्टों में फर्क इतना है कि सच्चर का आंकलन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित था, जबकि मिश्र आयोग ने सभी अल्पसंख्यक समुदायों और उनमें भी दलितों की बदहाल स्थिति का ब्यौरा दर्ज किया है।

कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का खेल, खेलते-खेलते निरंतर सिमटती जा रही है, बावजूद वह इस खेल से बाहर नहीं आना चाहती। यह स्थिति देश की एक बड़ी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

एम्स भोपाल द्वारा मुरैना जिले में रोटरी चिकित्सा मिशन 'राहत-2025' के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार

-समता पाठक

जगत प्रवाह, भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में, एम्स भोपाल की एक समर्पित डॉक्टरों की टीम मुरैना जिले में आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन- राहत-2025 के 26 मार्च से 02 अप्रैल 2025 तक चलने वाले मेगा हेल्थ कैंप में पूर्ण अवधि के लिए भाग ले रही है। इस मेगा हेल्थ कैंप का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। एम्स भोपाल की ओर से डॉ. अनिंदो मजूमदार, डॉ. अनंथन, डॉ. अदिति भारती, डॉ. कविता आर वी, डॉ. अग्निशिखा चौधरी, डॉ. वैष्णवी गावंडे, डॉ. कपिल प्रजापत और डॉ. आकांक्षा पाटिल जैसे अनुभवी चिकित्सक इस शिविर में क्लिनिकल कंसल्टेशन, रेफरल सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह का दृढ़ विश्वास है कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मानव सेवा का सबसे प्रभावी और उच्चतम रूप है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने 'वन स्टेट, वन हेल्थ पॉलिसी' की पहल को जन्म दिया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान, साक्ष्य-आधारित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना और राज्य भर में एक समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करना है। शिविर के पहले दो दिनों में ही लगभग 13,500 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इस मेगा हेल्थ कैंप में 36 सहयोगी अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों ने भाग लिया, जिनमें एम्स नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, पीजीआईएमईआर नई दिल्ली और बीएमएचआरसी भोपाल शामिल हैं। यह सामूहिक प्रयास मुरैना जिले के ग्रामीण और वंचित समुदायों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एम्स भोपाल और अन्य संस्थानों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वन भूमि पर संगठित अवैध कटाई अतिक्रमण उत्खनन परिवहन को संयुक्त प्रयासों से विफल किया जाए: कमिश्नर

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह, नर्मदापुरम। कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में वन विभाग की संभाग स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर ने वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से वन भूमि पर संगठित अवैध वृक्ष कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले लोगों को संयुक्त प्रयास से उनके मंसूबे विफल करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की वन क्षेत्र में अवैध कटाई अवैध उत्खनन एवं वन भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसकी प्रभावी रोकथाम की जाए। राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग इसमें अपना सहयोग देते हुए ऐसे प्रयासों को सख्ती से रोके। कमिश्नर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह वन विभाग के साथ वन क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्त कर विद्युत लाइनों को ट्रिपिंग से रोके एवं विद्युत लाइनों का रखरखाव समुचित रूप से करें। कमिश्नर ने कहा कि विद्युत लाइन के ट्रिपिंग को रोके ताकि वन्य एवं वन्य प्राणियों को विद्युत करंट से बचाया जा सके। कमिश्नर ने कहा कि विद्युत विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी वन विभाग के साथ संयुक्त गश्त कर वन अपराधियों द्वारा विद्युत लाइन से करंट लगाकर की जा रही अवैध शिकार गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए एवं विद्युत की अनियमित ट्रिपिंग होने पर इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों के साथ तत्काल साझा करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध शिकार गतिविधियों को प्राथमिकता से विफल किया जाए।

दुनिया भर में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण इसे संकट में डाल रहा है: डॉ. संदीप सबलोक

-संवाददाता

जगत प्रवाह, सागर। विश्व जल संरक्षण दिवस पर शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय की 11 एमपी बॉयज एवं 7 एमपी गर्ल्स बटालियन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. जीएस रोहित के निर्देशन में एनसीसी यूनिट के एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. जयनारायण यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. संदीप सबलोक ने कैडेट्स को जल संरक्षण की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. संदीप सबलोक ने एनसीसी कैडेट्स से कहा कि जल संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पानी जीवन का आधार है, फिर भी दुनिया भर में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण इसे संकट में डाल रहा है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और इसके अपव्यय को रोकना। डॉ. संदीप सबलोक ने कैडेट्स को बताया कि हम छोटे-छोटे प्रयासों से जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, जैसे नल को ठीक करना ताकि रिसाव न हो, वर्षा जल संचयन करना, और अनावश्यक रूप से पानी बहाने से बचना। कृषि में ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग भी पानी की बचत करता है। इसके अलावा, जागरूकता फैलाना और औद्योगिक स्तर पर जल प्रबंधन को बेहतर करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि हम आज जल संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे, तो भविष्य में पीने योग्य पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन सकती है। एनसीसी कैडेट के रूप में यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य संसाधन को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन कीर्ति रैकवार ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स ने जल संरक्षण के लिए जागरूकता प्रसार में अपना योगदान देने की शपथ ली।

सिविल लाइन पुलिस ने किया ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह, विदिशा। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें Grandexch नामक वेबसाइट के माध्यम से अवैध जुआ संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में थाना विदिशा देहात में अपराध क्रमांक 0221/2025 के तहत धारा 4A मध्यप्रदेश राज्य अधिनियम 1976 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के मार्गदर्शन में तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक विमलेश राय के नेतृत्व में जुआ सट्टा आईपीएल जैसे अपराधों में प्रभावी कारवाई हेतु एक विशेष टीम गठित की गई। दिनांक 28 मार्च 2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक विमलेश राय को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि Grandexch नामक वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल सिविल लाईन टीम के द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि Grandexch.com, Grandexch100.com, और Grandexh.com जैसे डोमेन के माध्यम से ऑनलाइन जुआ संचालित किया जा रहा था। सट्टा खेलने वालों से डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए अवैध रूप से पैसे एकत्र किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एसबीआई एटीएम के पास खंडेलवाल की दुकान में दो व्यक्ति चेन्नई और बेंगलुरु के आईपीएल मैच पर सट्टा का हार जीत का दावा लग रहे हैं। तत्काल टीम द्वारा मुखबिर सूचना के बताएं अनुसार उक्त स्थान पर पहुंचकर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया जो आईपीएल के चेन्नई एवं बेंगलुरु के मैच पर सट्टा लगा रहे थे तथा अपनी अपनी डायरी में लिख रहे थे।

उक्त दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम मनोज गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता उम्र 45 साल निवासी मां विहार कॉलोनी एवं दूसरे आरोपी ने अपना नाम इकबाल उर्फ इशान खान पिता सुलेमान उम्र 33 साल निवासी लोहंगी मोहल्ला विदिशा का होना बताया। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई जिसमें अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भी नाम आए है। तकनीकी विश्लेषण कर अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अवैध गतिविधियों में शामिल कर रहा था।

भारत सहित दूसरे देशों में होता जल संकट

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला "विश्व जल दिवस" वैश्विक जल संकट की एक भयावह याद दिलाता है जिसमें 220 करोड़ लोग अभी भी सुरक्षित और शुद्ध जल से वंचित हैं। पिछले कुछ वर्षों से ही पानी की कमी होती जा रही है चाहे वह सतही जल हो या भूजल। विश्व के कई हिस्सों बारिश की अनियमितता, भूजल स्तर में गिरावट और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की उपलब्धता गंभीर चिंता की विषय बन गई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पानी की कमी है। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों के बीच भी पानी की वजह से झगड़े होते रहे हैं। इजरायल, जॉर्डन, मिश्र और इथियोपिया जैसे कुछ अन्य देशों के बीच भी पानी की कमी हो गई है।

पेयजल के मामले पर "ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉटर" द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य दुनिया के सामने रखा गया था कि दुनिया भर में इस दशक के अंत तक ताजे पानी की आपूर्ति की मांग 40 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और पानी की कमी के साथ ही निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण आने वाले दो दशकों में खाद्यान्न उत्पादन काफी घट जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को भी इस वजह से खाद्य आपूर्ति में 16 प्रतिशत से अधिक की कमी का सामना करना पड़ेगा जिससे खाद्य असुरक्षित आबादी में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होगी। भारत में जल आपूर्ति की उपलब्धता 1,100 से 1,197 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच है और पानी की मांग भारत में 2010 के मुकाबले 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। वास्तविकता यही है कि जल संकट दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के लिए भी एक विकट समस्या बन चुका है। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ स्थिति बिगड़ने लगती है। भारत में वैश्विक जनसंख्या का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है जबकि भारत को केवल 04 प्रतिशत जल संस्थान ही उपलब्ध है। अटल भूजल योजना को देश भर में भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए चलाया जाना चाहिए। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने दुनिया और भारत में पानी की स्थिति के बारे में भयावह चित्र प्रस्तुत किया था। नदियों को भारत की जीवन रेखा माना जाता रहा है लेकिन इस सम्मेलन में कहा गया कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों में पानी कम होता जाएगा और 2050 तक पानी की उपलब्धता जरूरत से एक तिहाई कम रह जाएगा। करीब ढाई हजार किलोमीटर लंबी गंगा देश की सबसे प्रमुख नदी है जिस पर कई राज्यों में करोड़ों लोग निर्भर करते हैं। हिमालय में कुल 9,575 हिमनद (ग्लेशियर) हैं और नदियों में पानी हिमनदी से आता है। केवल उत्तराखंड में ही 968 हिमनद है लेकिन मौसम के असाधारण परिवर्तन के कारण हिमनद तेजी से पिघलने लगे हैं। पिछले 87 वर्षों में 30 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद का 1.75 किलोमीटर हिस्सा पिघल गया है। हिमनदों के तेजी से पिघलने से देश में पानी की भयावह किल्लत पैदा होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं।

वर्तमान में देश का लगभग एक तिहाई भाग या तो सूखाग्रस्त है या रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके कारण कृषि पर निर्भर समुदायों की विवशता बढ़ गई है और साथ ही स्रोतों का दोहन अधिक हो गया है जिससे संसाधनों का कुप्रबंधन हो रहा है और भूगर्भीय संकट उत्पन्न हो गया है। अति दोहन से जल दूषित हो रहा है और तब स्थिति और गंभीर हो जाती है जब समुदायों में जल सुरक्षा योजना से जुड़े पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य मानकों को कायम रखने के लिए आवश्यक जानकारी, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी होती है। भारत में पानी की जरूरत बढ़ रही है और देश की जीवन रेखा एक बेहद दबाव में है। दुनिया भर में हमारा वार्षिक भूजल दोहन सबसे अधिक है। जिस तरह से पानी हमसे दूर होता जा रहा है उससे पानी का मोल अब सभी को पहचानना होगा। हमें अनावश्यक रूप जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. टेहरी कला। करणी सेना ने राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन अनुविभाग अधिकारी पुलिस देवरी को सौंपा है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि सपा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के लिए अशोभनीय शब्द कहे। 23 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा देश के गौरव प्रतीक राणा सांगा के खिलाफ में अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जो कि घोर निंदनीय है। राणा सांगा न सिर्फ क्षत्रिय समाज बल्कि संपूर्ण देश की सनातनीय संस्कृति के ध्वज का वाहक हैं। इसलिए उन्हें हिंदू पद से नवाजा गया है। वीर शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये एवं उक्त सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की जावे। सांसद का उनके पद से इस्तीफा दिलवाया जाए एवं भीडिया के सामने आकर के संपूर्ण क्षत्रिय समाज एवं देश की जनता से माफी मांगे। ज्ञापन देने वालों में रवींद्र वेस, रोहित सिंह राजपूत, कुलदीप सिंह राजपूत, प्रीतम सिंह राजपूत, नेतराज सिंह राजपूत, सुत कुमार उपाध्याय, रुद्र राजपूत, सहित बड़ी संख्या में करणी सेना और हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे।

मालवीय मंडल प्रतिनिधि नियुक्त

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। केश शिल्पी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नन्द किशोर वर्मा ने जगदीश मालवीय को टिमरनी नगर परिषद में मंडल प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मालवीय केश शिल्पी बंधुओं की सहायता एवं केश शिल्पी कार्ड बनाना मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मंडल की अन्य योजनाओं एवं विश्वकर्मा योजना संबंधित कार्य करने हेतु मंडल प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मालवीय की नियुक्ति पर उनके मित्रों एवं स्वजातीय बंधुओं ने बधाई दी। बधाई देने वालों में रामा देवड़ा, जगदीश वर्मा, राम देवड़ा, रमन मालवीय, परसराम, सेन गोलू, सेन प्रकाश, देवड़ा गोलू, संतोष मालवीय, संतोष सेन, रवि पलुस्कर ,राम दास सेन, सुनील सेन ने मालवीय को बधाई दी एवं नन्द कुमार वर्मा का आभार माना।

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना, जिला पंचायत सदस्य डॉ. योगेश के गृह ग्राम की घटना

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. लहरिपुर। जिले की गाडरवारा तहसील ग्राम पंचायत बरहटा के ग्राम बरेली में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता पर दबाव बनाकर बात छुपाने की पुरजोर की गई। मामला संज्ञान में तब आया जब पीड़िता 06 माह की गर्भवती हो गयी, जब उसे अहसास हुआ एवं उसने परिजनों को डरते डरते यह बात बताई तब परिजनों द्वारा थाना गाडरवाड़ा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की घटना सितंबर की है।

पहले लक्कुश कहार नामक व्यक्ति ने पीड़िता को धान के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। फिर एक हफ्ते बाद नीरज कहार द्वारा पीड़िता का दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की उम्र 22-23 वर्ष है, वहीं पीड़िता नाबालिग 15 वर्ष की आयु आगे की जानकारी देते हुए एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि उन पर पास्को व बलात्कार का मामला कायम किया गया है एवं मेडिकल जांच के उपरांत गर्भ के समय की जानकारी मिलेगी, सूत्रों की माने तो मामले में अन्य नाम भी शामिल हैं जिन्हें दबावबश छिपाया जा रहा है। वहीं मामला ग्राम बरेली का है जो जिला पंचायत सदस्य भाजपा के नेता एवं शिक्षा एवं परिवहन मंत्री के बड़े ही करीबी डॉ. योगेश कौरव का गृह ग्राम है।

ऐसे में ये कहना कि सितंबर की घटना का इतने समय बाद सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण एवं जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता को आइना दिखाता है। जहां जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का बखान करते फिरते हैं। वहीं उनी के गांव में इतनी घिनौनी घटना का घटित हो जाना शर्मिन्दगी और अराजकता की पराकाष्ठा की चरम सीमा पर होने को दर्शाता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)